होने से संबंधित मामलों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में अतिदेय हो जाने वाले खातों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि क्रमशः 16484112 और 22988.84 करोड़ रुपये थी।

अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में उनके वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं:—

1. बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे एक तरफ, अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का पुनः निर्धारण करने में उनकी मदद करने तथा दूसरी तरफ, ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली बनाये।

2. अलग-अलग अग्रिमों के प्रभावी पर्यवेक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, उन अग्रिमों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए एक गहन तथा एक समान ग्रेडिंग पद्धति आरंभ करना।

3. प्रमुख अवरूद्ध खातों की वसूली संबंधी स्थिति पर नजर रखना।

4. जिन मामलों में खाते अवरूद्ध हो जाने का पता चल जाता है, उनमें उपचारी कार्रवाई करना।

हाल ही में, बैंकों को देय ऋण वसूली और उससे संबंधित और उसके प्रासंगिक मामलों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसुली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है।

Closure of rural Branches of Nationalised Bank in Punjab

96. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Nationalised Banks shifted/closed their rural branches in Punjab during the last 12 years due to terrorist activities, if so, the number of such branches;

(b) whether it is also a fact that these branches are not being shifted back/ reopened in those villages inspite of normalcy restored in Punjab and rural people are facing hardships due to this; and

(c) what immediate steps Governemnt are taking to reopen/shift back those branches in rural areas in Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Income tax defaulters

97. SHRI M.A. BABY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names and the amount of income tax dues against the top hundred I.T. defaulters;

(b) for how long these dues have been pending; and

(c) the steps being initiated and considered for realisation of the income tax dues from the defaulters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a). The names and the amount of income-tax dues against the top hundred I.T. defaulters, as per the latest available information as on 30-6-1993, are given in the annexed statement (*See* below).

(b) The outstanding tax in each case is composed of large items of demands. These demands relate to various assessment years and were raised in different financial years. The time and effort required to give the period of pendency of demand in each case will not be commensurate with the objective sought to be achieved.